

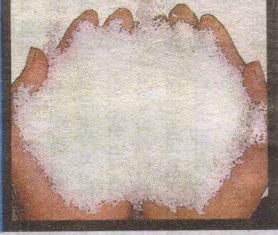
सियासत की भेंट चढ़ रहा चीनी उद्योग

चुनावी साल में गन्ना किसानों को लुभाने की राजनीतिक दलों में होड़

रंगराजन फार्मूला लागू कर तय किया जाए गन्ना मूल्य : इसमा

चीनी मिलों का बढ़ेगा घाटा, भुगतान न होने से गन्ना किसान भी रहेगा तंग

चीनी का गणित



2011-12 में चीनी मूल्य

₹31.50 प्रति किलो

2012-13 में मूल्य घटकर

₹29.50 प्रति किलो

हो सकता है एरियर

₹13,000 करोड़

उग्र की मिलों को हो सकता है घाटा

₹10,000 करोड़

चीनी उद्योग की मांग

- गन्ना मूल्य को चीनी मूल्य से जोड़ा जाए
- चीनी मूल्य का 75 फीसद हिस्सा किसानों को गन्ना मूल्य के रूप में मिले
- तीन फीसद के सोसाइटी कमीशन में छूट दी जाए
- बैंकों के कर्ज पर मिलों को व्याज सब्सिडी मिले

खास बातें

- महाराष्ट्र में चीनी की रिकवरी दर ज्यादा, गन्ना मूल्य कम
- उत्तर प्रदेश में कम रिकवरी दर पर गन्ना मूल्य ज्यादा
- मिलें सासत में, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से ठोस पहल नहीं
- गन्ना मूल्य घोषित किए बगैर पेरार्ड शुरू करने का दबाव

किसान संगठनों को एतराज
जहां तक किसान संगठनों का सवाल है तो वे भी पेरार्ड समय से शुरू करने के हक में हैं। लेकिन इसका फार्मूला पर उन्हें एतराज है। किसान जागृति मंच के संयोजक सुधीर पवार का कहना है कि किसान बाजार मूल्य के उतार-चढ़ाव को सहन नहीं कर सकता है। उन्हें रंगराजन फार्मूले पर भी आपत्ति है। उनका कहना है कि चीनी बनाने में 12 फीसद की लागत आती है, फिर मिलें अतिरिक्त 13 फीसद का फायदा क्यों चाहती हैं। अलबत्ता किसान नेता चाहते हैं कि सरकार को मिलें चलाने के लिए रास्ता निकालना चाहिए। चीनी उद्योग पर केंद्र की ओर से लगे नियंत्रण तो हटा लिए गए हैं, लेकिन एसएपी घोषित करने का राज्य सरकारों का अधिकार बना हुआ है।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : घाटे के दलदल में छटपटा रहा चीनी उद्योग चालू चुनावी साल में सियासत की भेंट चढ़ सकता है। सरकार की नीतियों के कारण चीनी मिल मालिक परेशान हैं। चीनी उद्योग को आधा अधूरा नियंत्रणमुक्त करने की वजह से उनकी मुश्किलें और भी गंभीर हो गई हैं। चीनी की उत्पादन लागत बढ़ी है। वहीं, खुले बाजार में चीनी की कीमतें पिछले साल के मुकाबले तेजी से कम हुई हैं। लिहाजा घाटा उठा रही मिलों के लिए इस बार पेरार्ड शुरू कर पाना भारी लगने लगा है। चुनावी साल में गन्ने को लेकर शुरू हुई सियासत भी चीनी उद्योग पर भारी पड़ रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य समर्थित मूल्य (एसएपी) घोषित किए बिना ही मिलों को चलाने का परमान जारी कर दिया है। ऐसे में मिलों के लिए गन्ने का पूरा भुगतान करना संभव नहीं होगा। एरियर बढ़ने से राज्य की चुनावी राजनीति पर उल्टा असर पड़ना तय है। राज्य सरकार के साथ हुई चीनी उद्योग संघ की बैठक नाकाम साबित हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश के गन्ना वाले गढ़ में डगमगाती अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत बनाने में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। उत्तर प्रदेश की

Dainik Jagran
(8/11/13)